we had taken the rubbish that was available because we were given free aid? What I understand is that something has to be bought and the hon. Minister went and bought it.

SHRI CHAND RAM: I categorically refute this. The ships that we are purchasing have been appreciated and rather they have been needed by the Shipping Corporation of India. They have made a technical study of it. They have been wanting these.

SHRI GIAN CHAND TOTU: May I know from the hon. Minister whether it is a fact that large contingents of officers had been going overseas to purchase ships and whether there is any ban on ministers going abroad in a democratic set up?

SHRI CHAND RAM: That is why we are going in for indigenous shipbuilding so that we may be able to make this country self-reliant and may not have to go in for the purchase of ships from abroad.

SHRI KRISHNARAO NARAYAN DHULAP: Sir, while replying to the question of Mr. Kalaniya, the hon. Minister stated that apart from the other countries he has also gone to Poland and a fifty-fifty per cent deal was struck because of his going there with the entourage. Now, I want to know how the price of those ships, which are to come from Poland, was fixed, and whether the price is going to be competitive or otherwise.

SHRI CHAND RAM: Sir, from Poland we did not purchase any ships as a result of my visit. As a result of my visit to Poland we did not purchase anything.

MR. CHAIRMAN: You have not purchased anything from Poland and, therefore, the question of comparison does not arise.

SHRI CHAND RAM: Sir, we have not purchased any ships from Poland.

**डा० भाई महावीर** : श्रीमन्, मंत्री जी ने कहा कि जो कीमत हमने दी है वह ग्रान्ट के रूप मे हमें मिली थी, इस वास्ते हमने जहाज खरीदा ही नहीं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या खरीदने का अर्थ यह नही कि इसमें जो कीमत चुकाई गई उसे चुकाने के लिए हमारे पास ग्रांट उपलब्ध थी? उसे खरीदने से पहले क्या यह उचित न होता कि हम उसकी कीमतो की पड़ताल करके सही कीमत तय करवाते ताकि अगर ग्रांट का एक ऐहसान भी होता है तो कम से कम ऐहसान लें। कृतज्ञता हो तो जो उचित है उतनी ही रहे। जितने अहसान जरूरी है उतना ही हम लें।

**श्री मोरारजी आर० देसाई** : सम्मानित सदस्य तो प्रोफेसर हैं, इतना तो उनको समझना चाहिए कि हमारे पास पैसा कम है और हम ऐसी ग्रांट मांगने नहीं जाते। उनको अपना शिप बेचना है, वही पैसा भी दे रहे हैं। हमें जो शिप मिल रहे हैं वे दूसरे के कंपैरिजन में अच्छे हैं। फिर कीमत का कहां सवाल पैदा होता है? हम ग्राट का ऐसा वितरण नहीं करेंगे। ग्राट हमको जो मिलती है उसको हम ग्रांट के तरीके से लेते हैं तो उसका यह मतलब नहीं कि हम लोगों से मुफ्त चाहते हैं। कोई देते हैं तो हम लेने से इंकार नहीं करते और इतना पैसा हम दूसरे देशों मे जहां जरूरत है वहां खर्चते भी हैं। इस तरह से हम इसका उपयोग करते है।

DR. BHAI MAHAVIR: Was it a tight grant?

**Complaints against freedom fighters**

*93. SHRI GRUDEV GUPTA:†
SHRIMATI HAMIDA HABIBULLAH:
SHRI SAWAISINGH SISODIA:
SHRI PRAKASH MEHROTRA:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of complaints which Government have received upto

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Gurudev Gupta.

March, 1978 against those freedom fighters who secured pension by producing bogus certificates regarding eligibility; and

(b) the number of cases investigated so far and the action taken thereon?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल)** : (क) तथा (ख). 31-3-1978 तक प्राप्त शिकायतों की संख्या 6817 है। विस्तृत जांच-पडताल और राज्य सरकारो के साथ परामर्श करने के बाद 456 मामलों में पेंशन रद्द कर दी गई है और पहले की गई अदायगियों की वसूली के आदेश दे दिये गये है। प्रत्येक मामले में उपलब्ध तथ्यों तथा सबूत को ध्यान में रखकर दांडिक अभियोजन का कार्य राज्य सरकारों पर छोड दिया गया है। 4749 मामलों मे प्रारम्भिक जाच के बाद पेंशन की स्वीकृति स्थगित कर दी गई है। राज्य सरकारों के परामर्श से विस्तृत जांच की जा रही है।

†[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): (a) and (b) The number of complaints received upto 31-3-1978 is 6,817. After detailed investigation and consultation with State Governments, pension has been cancelled and recovery of payments already made ordered in 456 cases. Criminal prosecution has been left to the State Governments to be undertaken in the light of facts and evidence available in each case. In 4749 cases, grant of pension has been suspended after preliminary examination. Detailed enquiries in consultation with the State Governments are in progress.]

**श्री गुरुदेव गुप्त** : मान्यवर, मंत्री महोदय ने बताया कि 6817 शिकायतों मे से 456 शिकयतों पर कार्यवाही की गई है और उनकी पेंशन रद्द की गई है। तो मैं यह जानना चाहूंगा कि इस गति से 6817 शिकायतों को निपटाने में वह कितना समय और चाहेंगे और दूसरे यह कि जिन अधिकारियों ने बिना पूरी छान-बीन किये स्वतंत्रता-सेनानियो को यह गलत पेंशन दी है और इस तरह का अनुत्तरदायित्वपूर्ण काम उन्होंने किया है, उन पर शासन क्या कार्यवाही करने का विचार रखता है?

**श्री धनिक लाल मंडल** : महोदय, जांच का जो तरीका है वह बहुत ही कम्बर्स है। क्योंकि जो भी शिकायतें आती हैं उन्हें हम राज्य सरकारों के पास भेजते हैं। हमारे यहा कोई दूसरा साधन नही है। राज्य सरकारों से उत्तर आने पर, प्राथमिक उत्तर आने पर हम तुरंत उसको स्थगित कर देते है, पेंशन की अदायगी जो हो रही होती है उसे स्थगित कर देते है। हमें उस व्यक्ति से भी पूछताछ करनी होती है, जवाब तलब करना होता है जिससे उनको अपनी स्थिति स्पष्ट करने का मौका मिले। इसी कारण समय लगता है लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसमें गति लाई जाए, तेजी लाई जाए।

**श्री गुरुदेव गुप्त** : मंत्री महोदय ने कहा है कि जांच बहुत कम्बरसम है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इसका प्रोसिजर क्या है, किस रूप से, किस प्रकार से यह जांच कराई जाती है और जांच कराने में कितना समय लग जाता है? मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस गति से काम चल रहा है क्या यह काम इन पांच वर्षों में जो जनता शासन का पीरियड है, पूरा हो जायेगा?

**श्री धनिक लाल मंडल** : महोदय, मैंने प्रोसिजर के संबंध मे जानकारी दे दी है। मैंने बताया है कि हम उनको राज्य सरकारों के पास भेजते हैं और जब वहां से जवाब आता है तो हम उसको स्थगित कर देते हैं लेकिन जिस व्यक्ति को पेंशन स्वीकृत की गई उसको भी मौका देते है ताकि वह अपनी स्थिति स्पष्ट कर सके। उसके बाद विस्तृत जांच करते हैं फिर उसको रद्द कर देते हैं। जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि इसमें गति

†[ ] English translation.

लाई जाए, इसके लिये हम कोशिश करेंगे। माननीय सदस्य ने जो यह पूछा है कि कितना समय लगेगा इसके लिये कुछ कहना मेरे लिये असंभव है लेकिन जो पेंशन स्वीकृत होती है, बिना उसको कारण बताओ नोटिस दिये, उसकी जांच किये बिना उसको खत्म नहीं किया जा सकता, रद्द नहीं किया जा सकता।

SHRI GURUDEV GUPTA: Sir, the second part of my question remains unreplied. The second part was, what action does the Government intend to take against those officers who are involved in sanctioning such pensions?

**श्री धनिक लाल मंडल** : उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि राज्य सरकारों से अनुशंसा होने पर ही हम स्वीकृति देते हैं।

SHRIMATI HAMIDA HABIBULLAH: Mr. Chairman, realising that there have been a number of complaints about some freedom-fighters, I find from personal as well as other reliable sources that a great deal of harassment is going on towards these freedom-fighters and sometimes there is a political angle to it as well. I would like to ask the hon. Minister whether he will look into this matter, because I know that it is creating a lot of discomfort and unhappiness.

**श्री धनिक लाल मंडल** : माननीय सदस्या के आरोपों का मैं प्रतिवाद करता हूं। माननीय सदस्या यदि कोई मामला मेरे सामने लायेंगी तो मैं उस पर जरूर कार्रवाई करूंगा।

**श्री सवाई सिंह सिसोदिया** : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि छः हजार शिकायतें आपके पास आई हैं यह आपने अभी बताया है तो मेरे प्रश्न का पहला हिस्सा यह है कि कुल कितनी पेंशन यहां से मंजूर की गई है और कितने व्यक्तियों को मिली है? दूसरे यह पूछना चाहता हूं कि ये जो शिकायतें आई हैं इनमें से कितनी शिकायतें गलत साबित हुई हैं और जो पेंशन स्वीकृत हुई है उसकी पहले पूरी जांच-पड़ताल केन्द्रीय स्तर पर हुई है या नहीं? तीसरे यह कि ये जो शिकायतें हैं इनका प्रान्तवाइज क्या ब्यौरा है इसको बताने की कृपा करें?

**श्री धनिक लाल मंडल**: महोदय, लगभग 1 लाख 17 हजार व्यक्तियों को पेंशन दी गई है, इतने लोगों को पेंशन स्वीकृत हुई है। जो शिकायतों के मामले हैं वह 6817 हैं। इनलोगों को गलत पेंशन स्वीकृत हुई है यह शिकायत है और इसमें से 456 मामलों में पेंशन कैंसिल कर दी गई है और 446 शिकायतों को गलत पाया गया इसलिये उनकी पेंशन रेस्टोर कर दी गई है। उनको पेंशन फिर से दे दी गई है। 5915 मामलों में जांच अभी चल रही है।

**श्री सवाई सिंह सिसोदिया** : जो शिकायतें आपके पास है उनकी जांच केन्द्रीय स्तर पर हुई है या नहीं?

**श्री धनिक लाल मंडल** : मैंने जैसा बताया कि राज्य सरकारों की अनुशंसा होने पर ही केन्द्रीय सरकार ने पेंशन की स्वीकृति दी है।

MR. CHAIRMAN: He has no information.

SHRI SAWAISINGH SISODIA: He has got those figures.

MR. CHAIRMAN: Have you got the figures from the various States? If you have got the list, you can place it on the Table of the House.

SHRI DHANIK LAL MANDAL: I will place it on the Table of the House.

SHRI JAGJIT SINGH ANAND. Sir, while I am one with the hon. Minister in cutting out all bogus cases and in hauling up not only the officials, but also the ex. MLAs, the ex. MPs, the MLAs and the MPs who issue bogus certificates I would like to draw the attention of the hon. Minister to the fact that in certain cases, on certain false technical

grounds the people who have already been drawing pensions have been deprived of their pensions their pensions have been stopped, though they are held to be freedom fighters by the State Governments and though they have got the certificates. They are deprived of their pensions on some small lacunae. I will mention one or two cases.

MR. CHAIRMAN: If you have one or two cases, you can mention them to him later on.

SHRI JAGJIT SINGH ANAND: Sir, while I would request him to concentrate on bogus cases, I would also request him to look into genuine cases. In the cases of those who have been in the INA, the Army and so on, on some small lacunae, they and their colleagues are denied pensions. On certain lacunae and on certain technicalities, their cases are rejected and they are not treated as freedom fighters.

SHRI DHANIK LAL MANDAL: Sir, I would like to assure the hon. Member, through you, that genuine freedom fighters will get pensions, irrespective of any lacunae or anything.

SHRI JAGJIT SINGH ANAND: Thank you very much.

SHRI MANUBHAI MOTILAL PATEL: Out of these 4,749 cases where the pension has been suspended, there are also cases which are real cases, where some old age pensioners, because they have not been able to get certificates and so on and because of certain technicalities, have been deprived of their pensions. I would like to know from the hon. Minister whether the conditions will be waived in such real cases.

SHRI DHANIK LAL MANDAL: Sir, I have already stated that genuine freedom fighters will be given pensions. If any hon. Member or anybody proves that a person is a freedom fighter, he will be given pension.

**श्री महेन्द्र मोहन मिश्र** : श्रीमन्, अभी मंत्री महोदय ने कहा है कि यह बड़ा कम्बरसम मैथड है। यह चिन्ता की बात है कि जिन 1 लाख 70 हजार लोगों को पेंशन दी गई है उनमें से बहुत से मामलों में जांच भी चल रही है। ऐसी स्थिति में मैं राज्य मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या इस संबंध में कोई जांच समिति गठित की गई है या केवल मात्र विभागीय जांच हो रही है ? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि जो स्टेटवाइज लिस्ट बनाई गई है उसके लिए भी क्या कोई जांच समिति गठित की गई है या विभाग के जो अधिकारी हैं उनके माध्यम से ही जांच हो रही है ?

**श्री धनिक लाल मंडल** : महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोई जांच समिति गठित नहीं की गई है। राज्य सरकारों से रिपोर्ट आने पर, जनता द्वारा कोई रिपोर्ट आने पर या शिकायत आने पर हम अपनी कार्यवाही करते हैं।

**श्री नागेश्वर प्रसाद शाही** : श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी इस बात से अवगत नहीं है कि पेंशन ग्रान्ट करने के पहले यहां जो व्यवस्था थी वह यह थी कि या तो जेल का कोई सर्टिफिकेट हो अथवा जेल में साथ रहे हुए किन्हीं दो एम०पीज० या एम०एल०एज० का सर्टिफिकेट हो ? उसमें राज्य सरकार की सिफारिश या जांच की कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन जहां पर इस प्रकार के सर्टिफिकेट न हो वहां पर राज्य सरकार से रिपोर्ट मंगाई जाती थी। ऐसी स्थिति में अगर कोई घपला हुआ है तो आपके कार्यालय में जो पेंशन ग्रान्ट करने वाले लोग है उनकी तरफ से हुआ है। इसके लिए आपका कार्यालय दोषी है क्योंकि बहुत सी पेंशनें बिना राज्य सरकारों की सिफारिश के मंजूर की गई हैं। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसे

मामले जो आपके कार्यालय के अधिकारियों की लापरवाही से हुए है उनकी संख्या कितनी है और उस संबंध में आपने क्या कार्यवाही की है? दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो फर्जी पेंशन लेने वाले हैं, मुझे यह कहने के लिए माफ करें, उनमें ज्यादातर लोग पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के है, दूसरे प्रान्तों के शायद ही कोई इक्का-दुक्का हों। इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के इस प्रकार के लोगों की संख्या क्या है? . . .

*(Interruptions)*

**श्री प्रभु सिंह** : हरियाणा के कोई बोगस केस नहीं हैं। वहां के सब मामले ठीक हैं।

*(Interruptions)*

**श्री धनिक लाल मंडल** : महोदय, यह बात सही है कि को-प्रिजनर्स के सार्टिफिकेट के आधार पर पेंशन स्वीकृत की गई है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो एम०पी० या एम० एल० ए० जेल में स्वयं रहे हुए हैं, यदि उन्होंने कोई ऐसा प्रमाण पत्र दिया है कि फलां व्यक्ति उनके साथ जेल में था, तो उनको भी पेंशन दी गई हैं, यह बात सही है। महोदय ये पेंशने केन्द्रीय सरकार के स्तर पर ही स्वीकृत नहीं हुई हैं, राज्य सरकारों के वेरीफिकेशन से ऐसा किया गया है। माननीय सदस्य ने हरियाणा और पंजाब की जो फीगर्स मांगी है, वह मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं।

MR. CHAIRMAN: I have already said that he could keep it on the Table of the House.

**श्री सतपाल मित्तल** : हरियाणा की फिगर्स जरूर रखी जांय। अभी माननीय सदस्य ने कहा कि हरियाणा में कोई भी नहीं है, इसलिये वहां की फिगर्स जरूर आनी चाहिए

**श्री धनिक लाल मंडल** : कुल 1874 दरख्वास्तें समय पर आई। समय के बाद 143 दरख्वास्तें आई, यानी टोटल दरख्वास्त 2021 आई। उनमें से सेंक्शन हुई 1279 और रिजेक्ट हुई 522 और 220 अभी अंडर कन्सीडेरेशन है *(Interruptions)* दिल्ली की फिगर्स हैं। जो कुल दरख्वास्तें आई उनकी सख्या है 2193 उनमें से 1561 मामलों में स्वीकृति दे दी गई है। 493 मामले रिजेक्ट कर दिये गये और 139 मामले विचाराधीन है, क्योंकि उनमे प्रमाण नहीं हैं।

**श्री सतपाल मित्तल** : हरियाणा में जो 220 मामले रिजेक्ट हुए है तो क्या वे टेक्नीकल ग्राउन्डस पर रिजेक्ट हुए हैं या बोगस थे।

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister, I have requested you to keep the whole list on the Table. Why are you taking the trouble unnecessarily?

SHRI L. R. NAIK: Sir, as the hon. Minister is aware, these pensions are being granted to freedom fighters both by the State Governments as well as by the Central Government. At the initial stage, of course, these pensions used to be granted only by the States. Subsequently, the Central Government came in a big way to help these freedom fighters for a very right cause, but what is happening is ....

MR. CHAIRMAN: What is the supplementary?

SHRI L. R. NAIK: My question is that whenever the State Government grants pension, automatically it must be sanctioned by the Central Government also. But what exactly is happening ....

MR. CHAIRMAN: Let it happen, but what is your question?

SHRI L. R. NAIK: My question is whether all those pensioners who are being granted pensions by the State Governments will automatically be given pension by the Central Government.

**श्री धनिक लाल मंडल :** महोदय, राज्य सरकारों ने जो पेंशन स्वीकृत की है, उसका आधार अलग है। हम लोगों का जो आधार है वह यह है कि "6 महीने जेल में जो रह आया है" इसमें जो कोई आ जाता है, उसको आटोमेटिकली हम ले लेते हैं।

SHRI GIAN CHAND TOTU: Sir, I know of a specific case where the Home Department has made allegation *ipso facto* to harass a Member of Parliament belonging to the Opposition party. I, therefore, want to know from the Minister whether it is a fact that the Home Department *ipso facto* is making allegations against members belonging to the opposition parties in the matter of allotment of *tamra patra* or pensions.

MR. CHAIRMAN: You can bring it to the notice of the hon. Minister.

SHRI GIAN CHAND TOTU: Let the hon. Minister reply.

**श्री धनिक लाल मंडल :** मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं और महोदय, मैं इसका प्रतिवाद करता हूं।

MR. CHAIRMAN: Next Question.

SHRI RAMANAND YADAV: Sir, . . .

MR. CHAIRMAN: Do you want to put a supplementary? All right.

**श्री रामानन्द यादव :** महोदय, यह केवल पेंशन देने के मामले में ही गड़बड़ी नहीं हुई है, बोगस्टी नहीं हुई है बल्कि प्रमाण-पत्र देने के मामले में भी गड़बड़ी हुई है। क्या सरकार इस बात की जांच करेगी कि भूतपूर्व स्पीकर लोक सभा श्री बलीराम भगत ने जो जेल नहीं गए थे जो फरार नहीं थे बोगस सर्टीफिकेट दे कर स्वतन्त्रता सेनानी ताम्रपत्र प्राप्त किया है ?

**श्री धनिक लाल मंडल :** सभापति महोदय, यह प्रश्न इस प्रश्न से नहीं उठता है।

(*Interruptions*)

**श्री मनुभाई मोतीलाल पटेल :** इंदिरा गांधी जेल नहीं गई फिर भी ताम्र पत्र ले लिया।

(*Interruptions*)

**श्री रामानन्द यादव :** क्या सरकार इस बात की जांच कराएगी . . .

(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: The Tamra Patra question does not arise out of this question.

**श्री रामानन्द यादव :** जिस आधार पर ताम्रपत्र दिया जाता है उसी आधार पर पेंशन दी जाती है . .

(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Next question. Shri K. N. Dhulap.

**Unemployment in the Rural Sector**

*94. SHRI KRISHNARAO NARAYAN DHULAP: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Central Government have recently made any survey to find out the incidence of unemployment in the rural sector in each State and Union Territory; and

(b) if so, what are the details of the findings of the survey?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI R. DESAI): (a) Yes, A sample house hold-survey on employment and unemployment is currently being conducted in both rural and urban areas of each State and Union Territory participating in the NSS programme in the 32nd round (July 1977—June 1978) of the National Sample Survey.

(b) The survey will be completed by 30th June 1978. The first results of this survey are likely to be available within a year of the close of the survey.

SHRI KRISHNARAO NARAYAN DHULAP: Sir, a survey is being conducted, but we should not wait upto the coming out of the survey on the figures of unemployment in the rural sector. We want to know what steps are being taken by the government to see that the